



सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020

प्रलिस के लिये:

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), मूल के नियम, सीबीआईसी।

मेन्स के लिये:

CAROTAR, 2020 के प्रावधान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** ने एक परपितर जारी किया जिसमें कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को **सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम (CAROTAR), 2020** को लागू करने में संवेदनशील होना चाहिये और प्रासंगिक व्यापार समझौतों या मूल नियमों के प्रशासन के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिये।

- राजस्व वभाग और आयातक के बीच संघर्ष के मामले में मूल/ओरजिनि देश के संबंध में एक **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** में नरिदषिट छूट लागू होगी।

CAROTAR नियम:

परचिय:

- CAROTAR, 2020 ने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात पर प्राथमकता दर की अनुमतके लिये 'मूल/ओरजिनि के नियमों' को लागू करने के लिये दशिया-नरिदेश नरिधारति कयि है।
- वे वभिनिन व्यापार समझौतों के तहत नरिधारति मौजूदा परचालन प्रमाणन प्रकरियाओं के पूरक है।
- इसे वतित मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2020 में अधसूचिति कयि गया था।

प्रावधान:

- एक आयातक को यह सुनिश्चिति करने के लिये कवि नरिधारति मूल मानदंडों को पूरा करते हैं इसकीउचति जाँच करना माल आयात करने से पहल आवश्यक है।
- एक आयातक को बलि ऑफ एंटरी में मूल से संबंधति कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसा किभूल प्रमाण पत्र में उपलब्ध है।
- आयातकों को यह सुनिश्चिति करना होगा किआयातति माल **मुक्त व्यापार संधियाँ (FTA)** के तहत सीमा शुल्क की रयियाती दर का लाभ उठाने के लिये नरिधारति 'मूल के नियम' प्रावधानों को पूरा करता है।
 - आयातकों को यह साबति करना होगा किआयातति उत्पादों का मूल देशों में कम से कम 35% मूल्यवर्धन हुआ है।
 - इससे पहले, नरियात के देश में एक अधसूचिति एजेंसी द्वारा जारी कयि गया **मूल देश का प्रमाण पत्र ही FTA** का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त था।
 - इसका कई मामलों में फायदा उठाय गया था, यानी FTA भागीदार देश ज़रूरी मूल्यवर्धन के लिये आवश्यक तकनीकी कषमता के बनिा प्रश्नगत माल का उत्पादन करने का दावा करते रहे हैं।

नहितारथ:

- वे आयातक को मूल देश का सही ढंग से पता लगाने, रयियाती शुल्क का उचति दावा करने और FTAs के तहत वैध आयात की सुचारू नकिसी में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिये मज़बूर करेंगे।
- उन्हें आयातक से मूल देश का सही ढंग से नरिधारण करने, रयियाती शुल्क का सही दावा करने और FTAs के तहत वैध आयातों की सुचारू नकिसी में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने की आवश्यकता होगी।
- घरेलू उद्योग को FTAs के दुरुपयोग से बचाया जाएगा।
- इन नियमों के तहत जिस देश ने भारत के साथ FTA कयि है, वह कसिी तीसरे देश के सामान को सरिफ लेबल लगाकर भारतीय बाज़ार में डंप नहीं कर सकता है।

मुक्त व्यापार समझौता:

परिचय:

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है। इसके तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है जिसके तहत दोनों देशों के मध्य उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ता हो जाता है।
- इसमें वस्तुओं का व्यापार (जैसे कृषि और औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं में व्यापार (जैसे बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) शामिल हैं।
 - इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति आदि जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं।
- भारत ने यू.ई., मॉरीशस, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और आसियान सदस्यों सहित कई देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किये हैं।

लाभ:

- टैरिफ और कुछ गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके एफटीए भागीदारों को एक दूसरे देशों में बाजार तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।
- निर्यातक बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के बजाय एफटीए को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें गैर-एफटीए सदस्य देश के प्रतिस्पर्धियों पर तरजीही उपचार मिलता है।

प्रश्न. 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' शब्द अक्सर कनि देशों के समूह के संदर्भ में समाचारों में आता है? (2016)

- (a) जी20
- (b) आसियान
- (c) शंघाई सहयोग संगठन
- (d) सार्क

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), आसियान के दस सदस्य देशों तथा पाँच अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।

अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/carotar-2020>